P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-9* May- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सन् 2000 के बाद भारत–अमेरिका सम्बन्ध : एक विश्लेषण

Indo-US Relations After 2000: An Analysis

Paper Submission: 20 /05/2020, Date of Acceptance: 23/05/2020, Date of Publication: 28/05/2020

बनवारीलाल मैनावत
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्तमान वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के युग में आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है। 2001 के बाद भारत–अमेरिका के सम्बन्धों में तेजी से बदलाव आया है। अमेरिका के लिए चीन जैसी नई आर्थिक शक्ति ने चुनौती पैदा की है। वहीं आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिका ने मुहिम छेड़ी है। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए एक मतबूत साथी देश के सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई है। भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त देश हो सकता है। वहीं भारत को भी आतंकवाद, चीन–पाक गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए आधुनिकृत महाशक्ति के सहयोग की जरूरत है। रूस अब मतबूत स्थिति में नहीं है। समयानुसार अमेरिका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस ओर कदम बढ़ाया गया था। डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ सम्बन्धों को मजबूती प्रदान की थी। सामरिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, व्यापारिक, स्वास्थ्य, नाभिकीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में कई संधियॉ की गई है। राष्ट्रपति ओबामा ने दोनों देशों के सम्बन्धों में मधुरता पैदा की है। प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रम्प ने उसी क्रम को ''हाउडी मोदी'' तथा ''नमस्ते ट्रंप'' के माध्यम से आगे बढाने का कार्य किया है। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, मध्य–पूर्व में शक्ति संतुलन बनाने हेतु भारत के आकार, भौगोलिक स्थिति, अर्थ व्यवस्था और सैन्य शक्ति डिप्लोमेटिक ताकत की दृष्टि से भारत ही अमेरिका के लिए उपयुक्त सहयोगी देश हो सकता है।

Economic competition has increased in the current globalization, liberalization and privatization era. India-US relations have changed rapidly since 2001. A new economic power like China poses a challenge for America. At the same time, the US has waged a campaign against terrorism. The need for the support of a strong partner country has been felt to establish its strong position in the Indo-Pacific region. India may be the most suitable country for this. At the same time, India also needs the cooperation of modernized superpower to counter terrorism, Sino-Pak alliance. Russia is no longer in a strong position. Efforts are on to build a good relationship with America over time. This step was taken by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Dr. Manmohan Singh strengthened relations with America. Many treaties have been made in the areas of strategic, technology, economic, commercial, health, nuclear energy etc. President Obama has created harmony in the relationship between the two countries. Prime Minister Modi and President Donald Trump have worked to advance the same order through "Howdy Modi" and "Namaste Trump". India can be a suitable ally for America in terms of size, geographical location, economy and military power diplomatic power to balance the power in Indo-Pacific region, Middle-East.

मुख्य शब्द : वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, नया परिवेश, आतंकवाद, व्यापारिक, सामरिक, प्रौद्योगिकी सम्बन्ध, जनरल सिक्योरिटी ऑन मिलिटरी इन्फोरमेशन एग्रीमेन्ट, परमाणु, नाभिकीय, समझौता, सूचना आदान–प्रदान, लॉजिस्टिक एक्सचैंज मेमोरेण्डम समझौता, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, चीन–पाक, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, टेक्स फोरम आदि।

Globalization, Liberalization, Privatization, New Environment, Terrorism, Business, Strategic, Technology Relations, General Security on Military Information

Agreement, Nuclear, Nuclear, Compromise, Information Exchange, Logistic Exchange Memorandum of Understanding, Indo-Pacific Region, China-Pakistan, Howdy Modi, Namaste Trump, Tex Forum etc.

प्रस्तावना

1990 से पूर्व भारत की स्वतंत्र एवं गुट निरपेक्ष विदेश नीति के कारण अमेरिका भारत को शंका की दृष्टि से देखता था। अमेरिका की नीति भारत के प्रति सकारात्मक नहीं रही थी। 1985 तथा अक्टूबर 1987 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेरिकी यात्राओं द्वारा दोनों के मध्य कटुता कम करने का प्रयास किया गया। किन्तु भारत की सोवियत के साथ संधी, अमेरिका का पाक के प्रति दृष्टिकोण, दियागों गार्सिया में अमेरिका के सैनिक अड्डे, भारत को दी जाने वाली सहायता में कटौती, बंग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के प्रति अमेरिका की नीति आदि कारणों से भारत–अमेरिका के सम्बन्ध मधुर नहीं बन सके थे। 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति को अपनाया जिससे भारत की विदेशनीति में भी बदलाव आया। इसके साथ ही भारत के सम्बन्ध अमेरिका के साथ सुधरने लगे, कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के दृष्टिकोण में बदलाव आया। 1991 में भारत–अमेरिका नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। किन्तु 1990 के दशक में भी सीटीबीटी, क्रायोजेनिक इंजन का मुद्दा, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण मुद्दा, कश्मीर मुद्दा तथा सुरक्षा परिषद की सदस्यता, कारगिल समस्या तथा 1998 का परमाणु परीक्षण आदि अनेक मुद्दे असंतोष के कारण रहे। इस दशक में दोनों देशों के सम्बन्ध काफी उतार–चढ़ाव के रहे। राष्ट्रपति क्लिंटन की मार्च 2000 में भारत की 5 दिवसीय यात्रा ने दोनों देशों के माध्य सम्बन्धों को नई दिशा देने का एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया। इसमें दोनों देशों के शासन प्रमुखों के बीच नियमित रूप से शिखर बैठक जारी रखने सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार पर चल रही बातचीत को गति प्रदान करने, आपसी मुद्दों की समीक्षा करने तथा आतंकवाद से मिलकर निपटने की सहमति बनी थी। 2001 के बाद भारत–अमेरिका सम्बन्धों में बदलाव तीव्रता से आया है। क्योंकि शीतयुद्ध के पश्चात वैश्विक अर्थ व्यवस्था उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की ओर बढ़ी है। अब अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए रूस के स्थान पर चीन जैसी उभरती शक्तियॉ बन गई है। इस बदले वैश्विक परिवेश ने अमेरिका तथा भारत दोनों को एक–दूसरे के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया है। 1991 के बाद भारत द्वारा अपनाई आर्थिक नीतियॉ अमेरिका की आर्थिक विचारधारा व हितों के अनुकूल है। क्योंकि भारत के रूप में अमेरिका को व्यापार तथा निवेश के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा था। साथ ही पहली बार अमेरिका ने उभरते हुए चीन के विरूद्ध एक शक्ति संतुलन बनाने के लिए भारत की भूमिका को महसूस किया। वहीं भारत ने भी महसूस किया है कि सामरिक दृष्टि से मजबूती लाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीक तथा आधुनिकीकृत हथियारों तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है जो अमेरिका से प्राप्त हो सकती है। साथ ही चीन–पाक का मुकाबला करने के लिए मजबूत साथी की जरूरत है। विश्व आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका का सहयोगी बनना जरूरी है। अफगान में आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने में अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए। इसके अलावा हिन्द महासागर में अमेरिका की सामरिक पहुँच बनाने के लिए भारत का सहयोग जरूरी है। भारत के मूल वासियों का एक बड़ा वोट बैंक अमेरिका में निवास करता है। उससे भी सम्बन्धों में मधुरता आई है। इस नये परिवेश के कारण दोनों देशों को नजदीक आने का वातावरण मिला है। पिछले दो दशकों में भारत–अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार हुआ है। अनेक मदभेदों के बाबजूद सामरिक सम्बन्धों की शुरूआत हुई है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान में विकसित हुए नये परिवेश में भारत–अमेरिका के बढ़ते सम्बन्धों का विश्लेषण एवं समयानुकूल उपयोगिता व एक दूसरे की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।

विषय विस्तार

सितम्बर 2001 को अमेरिका में आतंकी हमला हुआ जिससे अमेरिका हिल गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व आतंकवाद खत्म करने का प्रस्ताव पारित कराया। इस आतंकी हमले के विरूद्ध भारत ने अमेरिका का सहयोग देने का आश्वासन दिया। क्योंकि भारत स्वयं आतंकवादी घटनाओं से परेशान था। नवम्बर 2001 में राष्ट्रपति बुश तथा प्रधानमंत्री वाजपेयी के बीच बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करने की रूचि व्यक्त की थी। जनवरी 2002 मे रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नाडीज ने अमेरिका की यात्रा की तथा भारत–अमेरिका के मध्य ''जनरल सिक्योरिटी ऑन मिलिटरी इन्फोर्मेशन एग्रीमेंट ;ळैव्डप्।द्ध समझौता पर हस्ताक्षर किये। इससे दोनों देशों के मध्य हथियारों की तकनीक का परस्पर सौदा, खुफिया सूचना की रक्षा तथा हथियार खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों देशों के मध्य उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हुई और ठोस सहयोग की ओर कदम बढ़ाये। राष्ट्रपति जूनियर जॉर्ज बुश एवं उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने संदेश दिया था कि अमेरिका विदेश और सुरक्षा के मामलों में भारत को खास महत्व देता है। उसकी पॉलिसी में भारत के लिए खास जगह है। व्हाइट हाउस में 2002 के सितंबर में एक राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज तैयार किया था। उसमें भारत की चर्चा खास तौर पर नाम लेकर की गई थी। उसमें भारत को महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी कहा गया था। हॉलांकि उसके बाद एशियाई क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आये। उन बदलावों के बाद भी भारत के बृजेश मिश्र ने वाशिंगटन में बातचीत की और दूसरी ओर अमेरिका के अर्मिटेज ने भारत की यात्रा की थी। 2003 में भारत के उपप्रधानमंत्री आडवाणी ने अमेरिका की यात्रा की, राष्ट्रपति बुश ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनसे मुलाकात की। इसके अतिरिक्त 2003 में जी–8 के सम्मेलन में राष्ट्रपति जॉर्जबुश ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को भरोसा दिलाया कि जनरल मुशर्रफ को आतंकवाद रोकने के लिए कहेंगे। जनवरी 2004 में अमेरिका–भारत ने रणनीतिक साझेदारी में अगला कदम

(NSSP) बढ़ाया जो द्विपक्षीय सम्बन्धों के लिए मील का पत्थर तथा आगे की प्रगति का एक खाका बना। 28 जून 2005 को भारत–अमेरिका के मध्य 10 वर्षीय रक्षा–समझौता हुआ जिसने सम्बन्धों में नया आयाम प्रदान किया। सुरक्षा व्यापार के लिए ''डिफेंस प्राक्योरमेंट एण्ड प्रोडक्शन ग्रुप'' नाम से एक नये पैनल गठन का समझौता किया गया। इस पर रक्षामंत्री प्रणव मुखर्जी तथा अमेरिका के रम्सफील्ड के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इससे दोनों देशों के मध्य सामरिक साझेदारी शुरू हुई। 18–20 जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका की यात्रा की इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा समझौता किया था। यह डॉ. मनमोहन सिंह तथा राष्ट्रपति जॉर्जबुश के मध्य हुआ था। इसमें आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग तथा रक्षाक्षेत्र मे नए सम्बन्धों सहित 16 विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। मार्च 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत की यात्रा की तथा दोनों शासन प्रमुखों ने परमाणु ऊर्जा समझौता तथा आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक समझौतो को दुहराया गया। जिसमें कहा कि– दोनों देश आतंकवाद के विरूद्ध मुहिम में एक–दूसरे का सहयोग करेंगे। विज्ञान–प्रौद्योगिकी के लिए दोनों देशों का एक उच्च स्तरीय समूह गठित होगा। अमेरिका ने भारत को उच्च परमाणु प्रौद्योगिकी सम्पन्न एक जिम्मेदार राष्ट्र की मान्यता दी। भारतीय संगठनों पर से प्रतिबंध हटाए जायेंगे। भारत अपने सैन्य–असैन्य परमाणु कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऐजेन्सी को देगा। अमेरिका तारापुर ऊर्जा संयंत्र को ईंधन देने पर विचार करेगा। कश्मीर सहित भारत–पाक के द्विपक्षीय मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण असैन्य नाभिकीय समझौता की बातें निम्न प्रकार थी –

1. यह समझौता 40 वर्ष के लिए होगा और आवश्यकता पड़ने पर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे असैनिक उद्देश्य से चलाये जा रहे भारत के परमाणु कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
2. भारत–अमेरिका परमाणु व गैर परमाणु सामग्री का हस्तान्तरण करेंगे। इसमें केवल कम सम्बर्दित यूरेनियम की सप्लाई होगी। इस परमाणु ईंधन का उपयोग प्रायोगिक रियेक्टरों या बिजली पैदा करने वाले रियेक्टरों में किया जायेगा।
3. भारत अपने रियेक्टरों को सैन्य व असैन्य में वर्गीकृत करेगा।
4. भारत 2014 तक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत अपने विद्यमान 22 नाभिकीय रियेक्टरों में से 14 रियेक्टरों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेन्सी के सुरक्षा मानकों के दायरे में लाकर इन रियेक्टरों को निरीक्षण एवं सुदूर अनुश्रवण के लिए खोल देगा।
5. भविष्य में स्थापित होने वाले रियेक्टरों को सैन्य अथवा असैन्य वर्ग में रखने का अधिकार भारत का होगा।
6. यह समझौता परमाणु बम बनाने या इसे बनाने की क्षमता रखने के भारत के अधिकार को स्वीकार करता है।
7. भारत अपने 'फास्ट–ब्रीडर रियेक्टरों' को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण के दायरे से बाहर रखने के लिए स्वतंत्र है।
8. नाभिकीय ईंधन एवं नाभिकीय ऊर्जा के विकास से सम्बन्धित सामग्री तथा नाभिकीय विद्युत प्लान्टों के निर्यात के मामले में भारत नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के मानकों को अपनायेगा। इसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के असैन्य रियेक्टरों को सम्बन्धित यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। इसके लिए अमेरिका अपने नाभिकीय अप्रसार नियमों व कानूनों को संशोधित करेगा।
9. भारत किसी भी स्तर पर अपनी नाभिकीय ऊर्जा क्षमताओं को असैन्य एवं शांतिपूर्ण कार्यों से हटाकर सैन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं करेगा।
10. नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति में किसी भी स्तर पर कोई बाधा उत्पन्न होने पर भारत इस समझौते की अन्य शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
11. यह समझौता भारत को अपना न्यूनतम सामरिक संहारक कार्यक्रम जारी रखने का भी अधिकार प्रदान करता है।

इस समझौते द्वारा भारत ने अपने फास्ट रियेक्टर व सैन्य परमाणु कार्यक्रम से सम्बन्धित परमाणु संयंत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजेन्सी की निगरानी से अलग रखा है। यह समझौता मनमोहन सरकार का तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत बडा कदम था। अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति के साथ ही भारत–अमेरिका के बीच 2008 में शांतिपूर्ण आणविक सहयोग समझौता पूर्ण हो गया। यह अमेरिका के विशेष प्रयासों से सम्भव हो पाया। इस समझौते का भारत के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा 1974 से चला आ रहा भारत का परमाणु अलगाव समाप्त हो गया तथा भारत ने इस समझौते के आधार पर ही विभिन्न देशों के साथ सिविल परमाणु सहयोग की प्रक्रिया शुरू की है। इस पर तत्कालीन विदेशमंत्री प्रणव मुखर्जी तथा अमेरिका के सचिव कोडोंलीजा राइस ने हस्ताक्षर किये थे। डॉ मनमोहन सिंह द्वारा जूनियर जॉर्ज बुश के साथ परमाणु समझौता किया जाना इसलिए महत्वपूर्ण था कि पड़ौसी चीन जैसी महाशक्ति का मुकाबला करने तथा आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए अमेरिका के साथ परमाणु समझौता एक मात्र विकल्प था। इसके अतिरिक्त यह समझौता–

1. भारत–अमेरिका परमाणु समझौता 2005–06 केवल बिजली उत्पन्न करने के उद्देश्य से नहीं हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों में मनमोहन सरकार का बडा कदम था। यह पहला मौका था जब भारत–अमेरिका के मध्य किसी ऐसी द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किये जिसके गहरे सामरिक प्रभाव थे। इस निर्णय के समय मनमोहन सरकार को वामपंथियों तथा मुस्लिमों की आलोचना का सामना करना पडा था। दूसरी ओर अमेरिका पर भरोसा करना चुनौती था। इससे अमेरिकी विरोध भी समाप्त हो गया।
2. दूसरा लाभ – भारत को परमाणु हथियार सम्पन्न देशों में गिने जाने की मान्यता मिल गई। साथ ही

परमाणु अप्रसार वाले देशों की मान्यता मिली, अब भारत परमाणु कारोबार व तकनीकी हस्तान्तरण करने वाले देशों में सम्मिलित हुआ।

3. घरेलू लाभ के रूप में फायदा यह हुआ कि देश का परमाणु कार्यक्रम, उसकी फंण्डिग और उसका प्रदर्शन सब पारदर्शिता के दायरे में आ गये।
4. इससे सामरिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में लाभ हुआ क्योंकि हकीकत में यह सामरिक संधि थी एवं अमेरिका की तकनीकी और उपकरण देने की शंका तेजी से कम हुई। जिस अमेरिका ने 1980 के दशक में सुपर कम्प्यूटर तक को भारत को देने से इन्कार कर दिया। उससे अब सर्वाधिक संवेदनशील सैन्य तकनीकी डेटा और खुफिया जानकारी साझा हो रही थी।
5. पाक से अलग होते हुए सावधनी से भारत के साथ ऐसा समझौता पहलीवार किया जिसे पाक के साथ भी अमेरिका ने साझा नहीं किया था।
6. वामपंथी विरोध का सामना करते हुए यह समझौता था, इसके बाद वामपंथ भारत में पस्त हो गया। सरकार गिराने का प्रयास भी नाकाम रहा और पश्चिम बंगाल में से भी वामपंथ सत्ता खो बैठा।

सच्चे अर्थों में भारत–अमेरिका के मैत्री सम्बन्धों का यह समझौता मील का पत्थर था, जब डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी पूरी साख दाव पर लगाकर अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। इसके बाद भारत–अमेरिका के सम्बन्ध गहरे होने लगे। नवम्बर 2009 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा की। 24 नवम्बर 2009 को राष्ट्रपति ओबामा के साथ व्हाइट हाउस में हुई वार्ता के बाद छः समझौतों पर हस्ताक्षर किये (1) वैश्विक सुरक्षा का विस्तार व आतंकवाद से मुकाबला (2) सूचना साझा करना व क्षमता निर्माण करना। (3) शिक्षा और विकास (4) स्वास्थ्य (5) आर्थिक व्यापार एवं (6) कृषि एवं हरि सहयोग आदि हुए। दोनों देशों के बीच आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक सहमति पत्र भी हस्ताक्षर किये गये। 2010 में भारत–अमेरिका के बीच सामरिक वार्ता का पहला दौर 4 जून 2010 को वाशिंगटन में सम्पन्न हुआ। वार्ता के शिष्ट मण्डल का नेतृत्व विदेशमंत्री एस.एस. कृष्णा तथा समकक्ष हिलेरी क्लिंटन ने किया। आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष, निरस्तीकरण, नाभिकीय अप्रसार, सुरक्षा परिषद में सुधार, व्यापार एवं निवेश, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान–प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए चर्चा इस वार्ता में की गई। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के मालमे में अमेरिकी रुख में नरमाई का संकेत भी वार्ता में मिला। नवम्बर 2010 में राष्ट्रपति ओबामा तीन दिवसीय भारत यात्रा पर रहे। यात्रा के पहले ही दिन दोनों देशों की कम्पनियों के बीच बीस ऐसे समझौते सम्पन्न हुए जिनसे अमेरिका में रोजगार के लगभग 50,000 नये अवसर सृजित हो सकेंगे। राष्ट्रपति ओबामा ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। ओबामा ने 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की। ओबामा प्रशासन में भारतीय मूल के अमेरिकी अधिकारियों की संख्या भी बढा दी गई थी। जो कि उस समय तक का सबसे बड़ा ऑकडा था। वर्ष 2011 में अमेरिका 100 विलियम अमेरिकी डॉलर से अधिक वस्तु एवं सेवा व्यापार सहित भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहभागी बना रहा। वर्ष 2012–13 के दौरान भारतीय तथा अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता से 2 विलियन अमेरिकी डॉलर की अब संरचना ऋण कोष, 20 मिलीयन अमेरिकी डॉलर की राशि से पॉच वर्षीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम शुरू हुआ तथा द्विपक्षीय असैनिक ऊर्जा करार 2008 को लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। हिन्द महासागर से पश्चिम प्रशांत सागर तक सामरिक स्थिति समान होने के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता में भारत की अहम भूमिका है। जनवरी 2015 में बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान भारत व अमेरिका ने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में साझा सामरिक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे, तथा इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने पर बल दिया था। 2015 में इस पर सहमति बनी थी कि दोनों देश एक दूसरे के यहॉ सशस्त्र सेनाओं के रूकने की व्यवस्था करेंगे। अमेरिका ने भारत को प्रतिरक्षा साझेदार घोषित कर दिया है। इसमें भारत का निहितार्थ यह है कि अमेरिका भारत को संवेदनशील प्रतिरक्षा तकनीक का हस्तान्तरण भी कर सकता है। साथ ही दोनों देशों ने 2005 में उनके बीच हुए 10 वर्षीय प्रतिरक्षा सहयोग समझौते को आगामी 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। अब यह 2025 तक मान्य रहेगा। जून 2015 में अमेरिकी रक्षा सचिव एस्टन कार्टर ने भारत का दौरा किया। यह भारतीय सैन्य कमान का दौरा करने वाले पहले रक्षा सचिव थे। इसी प्रकार भारत के मनोहर परिकर ने भी अमेरिका की प्रशांत कमान का दौरा किया। ऐसा करने वाले ये पहले रक्षामंत्री थे। 29 अगस्त 2016 को भारत–अमेरिका के बीच ''लॉजिस्टिक एक्सचैंज मैमोरेण्डम समझौता'' ;स्म्डव्द्ध किया गया है। यह एशिया क्षेत्र में शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण कदम है। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन का एकाधिकार खत्म होगा व शक्ति संतुलन बनेगा। यह दोनों देशों की सेना को फिर से ईंधन आपूर्ति करने या मरम्मत करने के लिए एक–दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। हॉलाकि उपयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारत हिन्द महासागर में महत्वूर्ण भूमिका निभा सकेगा तथा अमेरिका को भी इस क्षेत्र में निगरानी रखने की सुविधा रहेगी। अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया है। दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका का अमेरिका ने समर्थन किया है। प्रतिरक्षा सहयोग के अन्तर्गत दोनों देशों द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास के क्रम को जारी रखते हुए इसका विस्तार किया है। इसके अन्तर्गत दोनों देश मालावार नौ–सैनिक अभ्यास का संचालन नियमित रूप से कर रहे है तथा 2016 में इसमें जापान को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसी वर्ष (2016) में अमेरिका ने जापान तथा आस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण चीन सागर में गस्तीदल में भारत को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। किन्तु भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया था, यह कहते

हुए कि भारत संयुक्त गस्तीदल का हिस्सा कभी नहीं बनता है केवल संयुक्त सैनिक अभ्यास कर सकता है।

अगस्त 2017 में अमेरिका द्वारा जारी अपनी दक्षिण एशिया नीति दस्तावेज में अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका बढ़ाये जाने का समर्थन किया था। लम्बे विचार विमर्श के बाद अमेरिका द्वारा 18 सितम्बर 2017 को नई सुरक्षा नीति की घोषणा की है। इस रणनीति में ''अमेरिका पहले'' के विचार को लागू किया गया तथा अमेरिकी विदेशनीति में बहुपक्षीयता के विचार को गौण कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें भारत को प्रमुख सामरिक व प्रतिरक्षा सहयोगी देश घोषित किया गया है। इस प्रकार नई सुरक्षा नीति में भी भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी बताते हुए उसकी अग्रणी भूमिका का समर्थन किया गया है। दोनों देशों ने एशिया प्रशान्त व हिन्द सागर के संयुक्त सामरिक दृष्टिकोण की भी घोषणा की है। 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आशियान शिखर सम्मेलन में चार देशों के समूह क्वाड ;फन्।क्द्ध का विचार प्रस्तुत किया। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान तथा आस्ट्रेलिया चार देश सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य चारों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाना है। चीन ने इसका तीव्र विरोध किया था और अपने हितों के विरूद्ध माना। अमेरिका जानता है कि चीन के सैनिक व आर्थिक उदय ने अमेरिका के लिए नई चुनौती पेश कर दी है। वर्तमान में अमेरिकी नीति निर्माताओं का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक व सैनक दृष्टि से उभरता हुआ चीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती है। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में भारत जापान और आस्ट्रेलिया ही वे देश है, जो चीन को संतुलित कर सकते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह इसमें केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है। भारत को भी चीन–पाक के गढ़जोड का मुकाबला करने के लिए इसकी आवश्यकता है। अमेरिका के रक्षामंत्री जिम मैटिस व विदेश मंत्री पॉम्पियो तथा भारत के रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के मध्य वर्ष 2018 में ;22द्ध बैठक हुई। इसमें संवाद के दौरान संचार संगतता और सुरक्षा समझौता हुआ ;ब्व्डब्।द्ध। यह द्विपक्षीय बहुपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान अनुमोदित उपकरणों को सुरक्षित साझा करने और सूचनाओं के आदान–प्रदान करने के लिए दोनों देशों को सहयोगी बनाता है। इसके अतिरिक्त ''बैसिक एक्सचैंज एण्ड कॉओ परेशान एग्रीमेंट **(BECA)** पर भी दोनों पक्षों में वार्ता चलती रही है। इसके अन्तर्गत भारत–अमेरिका नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस ऐजेन्सी के बीच अवर्गीकृत व नियंत्रित वर्गीकृत भू–स्थानिक उत्पादों, स्थलाकृतिक, समुद्री और वैमानिकी डेटा, उत्पादों और सेवाओं के आदान–प्रदान की अमुमति दे सकेंगे। रक्षामंत्री परिकर ने स्म्डव्। पर हस्ताक्षर के समय कहा था कि भारत अंततः शेष समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की यात्रा दो बार की थी। एक बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री थे। बराक ओबामा की भाईचारे की भाषा ने सम्बन्धों को आगे बढाया। भारत की उदारता तथा खुलेपन की प्रशंसा की थी तथा भारतीय अनेक हस्थियों के उदाहरण देकर सौहार्द का वातावरण बनाया। भारत–अमेरिका के सम्बन्धों को मित्रता के उच्च स्तर पर ले जाने में ओबामा काल सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपनी विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन को भारत भेजा जाना व ओबामा प्रशासन के अमेरिकी उच्च अधिकारियों को भारत की कई यात्रायें कराया जाना तथा प्रगाढ़ सम्बन्धों की पृष्ठ भूमि तैयार की थी। भारतीय निवेश को अमेरिका में बढ़ावा दिया था। मानव संसाधन के रूप में भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स और व्यवसायियों की संख्या ओबामा काल में बडी तथा सम्बन्धों में प्रगाढता बढ़ी। द्विपक्षीय सम्बन्धों के सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर. पॉम्पियों ने 25–27 जून 2019 में भारत की यात्रा की। इसका उद्देश्य भारत–अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में नये तरीकों की खोज तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों सहित आपसी हितों के मामले पर उच्च स्तरीय सम्पर्क जारी रखना था। दोनों देश के नेताओं के मध्य ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, सीमापार आतंकवाद अफगानिस्तान, खाड़ी देशों एवं हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र आदि मुद्दों पर वार्ता हुई। इसमें अमेरिका ने भारत द्वारा रूस के साथ ''एन्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम''ै.400 समझौते को भारत की रक्षा जरूरत बताते हुए समयानुकूल माना। 17–19 सितम्बर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 74वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका यात्रा की। इसके अतिरिक्त ह्युस्टन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को ''हाउडी–मोदी'' के तहत सम्बोधन किया था। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मोदी जी की विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई। आतंकवाद मुद्दा भी इसमें शामिल था। वार्ता में भारत के साथ शीघ्र द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये जाने की ट्रंप ने आशा व्यक्त की थी। दोनों शासन प्रमुखों ने एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत–अमेरिका साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्पेस टैक्नोलॉजी और व्यापार भारत–अमेरिका सम्बन्धों के चार प्रमुख स्तम्भ है। दोनों देशों में सम्बन्ध बढ़ाने का विचार इन्हीं आधारों पर किया जाता है। विदेश नीति में निरन्तरता जरूरी है, और यही नीति आगे ले जाने की कोशिश नरेन्द्र मोदी ने की है। हॉलांकि, जिस समय ट्रम्प राष्ट्रपति बने उसके शुरूआती दौर में भारत के लिए ठीक समय नहीं रहा। ट्रम्प के कई फैसले भारत के पक्ष में नहीं थे। बाद में सम्बन्ध सुधरते गये। फरवरी 2020 को ट्रम्प की भारत यात्रा ''नमस्ते ट्रम्प'' उनका चुनावी अभियान माना जा सकता है, क्योंकि 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने है। भारतीय मूल के 40–50 लाख लोग अमेरिका में निवास करते हैं। उस वोट बैंक को ट्रम्प अपनी झोली में डालना चाहते हैं। हॉलांकि ट्रम्प की भारत यात्रा से पूर्व उनके अनेक वक्तव्य भारत के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के आये थे। यह माना जा सकता है कि लोकतंत्र की विसंगतियों का सामना करते हुए तथा लोकतंत्र की सुन्दर पुस्तकीय धारणाओं को एक–एक करके धाराशाही होते देखकर भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों को भविष्य के लिए आशा व विश्वास का वातावरण बनाना पड़ता है। सत्ता में रहते हुए हर नेतृत्व इस दायित्व से बॅध जाता है।

अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के लिए मोदी इसी परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं। अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट मैदान में आयोजित ''नमस्ते ट्रम्प'' कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रम्प ने लोकतंत्र के इसी महत्व पर अपना सार्वजनिक सम्बोधन केन्द्रित रखा। मोदी ने भी लोकतंत्र की इसी पुस्तकीय सुन्दरता पर अपने भाषण को केन्द्रित रखकर ट्रम्प का स्वागत और धन्यवाद किया था।

ट्रम्प की भारत यात्रा से ट्रम्प के वे सारे भ्रम टूट गये जो भारत विरोधियों द्वारा देश विदेश में चलाये गये दुष्प्रचार के कारण उनके मन मस्तिस्क में घूर्णन कर रहे थे। ट्रम्प के हाव–भाव से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि वे भारतीयों द्वारा कियं गये स्वागत से गद्–गद् है। इससे दोनों देशों के मध्य समझ बढ़ी है। यद्यपि अभी ट्रम्प का ध्यान 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों पर था। फिर भी उन्होंने ''नमस्ते ट्रम्प'' के मंच से रक्षा समझौतों को पारित कराने की मौखिक स्वीकृति अवश्य दे दी थी। आगे यदि भारत–अमेरिका ''स्ट्रेटोजिक पार्टनरशिप फोरम'' का संज्ञान लिया जाय तो दोनों देशों का ध्यान अमेरिका–भारत टैक्स फोरम आरम्भ करने पर भी जा सकता है। इस दृष्टि से देखने पर यही संकेत मिलता है कि दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार का सुगम प्रबन्ध हो। ताकि व्यापारिक अभिक्रियाओं का अपेक्षित लाभांश प्राप्त किया जा सके। रक्षा, सुरक्षा से लेकर ऊर्जा और अन्तरिक्ष कार्यक्रमों तक की साझीदारी का निर्वहन दोनों देश तब ही भलिभॉति कर सकते हैं। जब वे व्यापार में लाभान्वित होंगे। इसलिए दोनों देश आयात–निर्यात, कराधान, दोहरा कराधान, शुल्क छूट इत्यादि विशंगतियों के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करते हुए विशुद्ध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से टैक्स फोरम खोले जाने को लेकर अधिक सक्रिय है। इस्लामिक आतंक के सम्बन्ध में अमेरिका में भी दोनों नेताओं ने एक साझा संकल्प दिखाया था और अब मोटोरा स्टेडियम से भी ट्रम्प ने इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। कश्मीर के 370 तथा अनु. 35ए के हटाये जाने तथा सीएए विरोधी दिल्ली दंगों पर भी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह उनकी स्व प्रकृति के विपरीत उनकी समझदारी दर्शाता है।

निष्कर्ष

किंगस कॉलेज लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रोफेसर हर्ष बी.पंत ने अमेरिकी राजनीतिक योजना के लिए भारत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि ''इण्डो–पैशिफिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शक्ति संतुलन बनाने के लिए तथा अमेरिका की क्षमता बढाने के लिए भारत महत्वपूर्ण है।'' इस क्षेत्र में चीन का सामना करने के लिए भारत की भागीदारिता से ही संसाधन पूर्ति की जा सकती है। अमेरिका भारत को अपने रणनीतिक हितों की कुंजी की मान्यता देता है। भारत के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है और दोनों ही प्रतिनित्यात्मक सरकार के संचालक व अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्द महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गो के माध्यम से वाणिज्य–व्यापार एवं संसाधनों के मुक्त प्रवाह में अमेरिका और भारत दोनों का साझा हित है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद मधुर सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विश्वास रखने वालों का मानना है कि ''हाउदी मोदी'' से लेकर ''नमस्ते ट्रम्प'' तक दोनों देशों के मध्य कई क्षेत्रों में प्रगति व अनेक साझेदारियॉ हुई है और हो रही है। आगे भी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आयेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. *डॉ. फडिया, बी.एल. ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा*
2. *डॉ. जोशी, आर.आरपी एवं अग्रवाल अनिता ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' शील संस प्रकाशन जयपुर।*
3. *डॉ. सिंहल, एस.पी. ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।*
4. *खण्डेला, मानचन्द, ''भारतीय राजनीति का भविष्य'' अरिहन्त पब्लिसिंग हाउस, जयपुर।*
5. *अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण 2019, समसामयिक वार्षिकी।*
6. *अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण 2020, समसामयिक वार्षिकी।*
7. *रहीस सिंह, विदेश मामलों के विशेषज्ञ का लेख दैनिक भास्कर दिनांक 01.03.2020*
8. *विवेक कुमार बडौला के विचार, दैनिक नवज्योति 4 मार्च 2020*
9. *संजय आवटे, स्टेट एडिटर, दिव्य मराठी के विचार, दैनिक भास्कर 28 मार्च 2020*
10. *एलियट एकरमैन के विचार, दैनिक भास्कर, दिनांक 20 अक्टूबर 2019*
11. *शेखर गुप्ता, एडीटर इन चीफ द प्रिन्ट के विचार, दैनिक भास्कर दिनांक 25 फरवरी 2020*
12. *हर्ष बी.पंत, प्रोफेसर किंगसकॉलेज लंदन के विचार, दैनिक भास्कर 03.11.2019*
13. *वेदप्रताप वैदिक, भारतीय विदेशनीति परिषद अध्यक्ष के विचार, दैनिक भास्कर दि. 04.03.20*
14. *NIC Internet google vkfn*